>

Title: Need to increase the Minimum Support Price of agricultural products in the country and to link rivers in the country.

**श्री हरिभाऊ जावले (रावेर):** अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश में मानसून की अनिश्चिता तथा किसी एरिया में सूखा और किसी एरिया में बाढ़ की समस्या है। मैं आपके माध्यम से एक गम्भीर समस्या सदन और सरकार के सामने रखना चाहता हूं। बाढ़ और सूखे का सामना देश के 60 प्रतिशत किसानों और देहात के किसान मजदूरों को करना पड रहा है। एक आसमानी संकट है और दूसरा सुल्तानी संकट है। सूखा और बाढ आसमानी संकट है। अभी सभी राज्य सरकारें इसके लिए केन्द्र सरकार से राहत मांग रही हैं।

महोदया, आदरणीय अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने बाढ़ और सूखे की समस्या मिटाने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना की शुरूआत की थी। उसका सर्वेक्षण भी किया था और उसके लिए समिति का निर्माण भी किया था। लेकिन यूपीए-1 और 2 ने नदियों को जोड़ने की योजना बंद कर दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि नदियों को जोड़ने की योजना को फिर से प्रारम्भ किया जाना चाहिए। सरकार को इस आफत, जो हमेशा भूतकाल में भी आ गई है और भविष्य में भी आएगी, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि क्लाइमेट चैंजिस की वजह से भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। इस आफ़त से निबटने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना तुरन्त शुरू कर दी जानी चाहिए।

महोदया, मेरी प्रमुख समस्या मिनीमम सपोर्ट प्राइज़ को लेकर है। मैं आदरणीय शरद पवार जी से पूछना चाहता हूं, उनके पास कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी है। एक जगह सूखा पड़ रहा है और दूसरी जगह रसायनिक खादों की कीमत बढ़ रही है, मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है, बिजली में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किसानों के मिनीमम सपोर्ट प्राइज में जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई है। अगर रसायनिक खादों में दुगुनी बढ़ोतरी हुई है तो मिनीमम सपोर्ट प्राइज में भी दुगुनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ज्वार, बाजरा या किसानों के जो भी उत्पाद हैं, उनके समर्थन मूल्य में दुगुनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, यह मेरी सरकार से मांग है। आदरणीय कृषि मंत्री जी ने दस बार समिति का बहिष्कार किया है, जिसमें से नौ बार समिति का बहिष्कार किसानों को राहत मिलने के लिए किया है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि कृषि मंत्री पवार साहब की भी डिमांड है कि कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए, उसको दुगुना बढ़ाना चाहिए।